Publication	Hindustan
Edition	Ghaziabad
Language/Frequency	Hindi/Daily
Page No	01
Date	30th April 2019

हिन्दुस्तान

रैपिड रेल को सभी विभागों ने दी हरी झंडी

गाजियाबाद/मेरठ | हिटी

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार के सभी विभागों ने सोमवार को हरी झंडी दे दी। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने प्रमुख सचिवों से कहा कि जो भी बाधाएं हैं तो उसे तत्काल निस्तारित किया जाए। यह सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।

सोमवार को लखनऊ में मुख्य सचिव के स्तर पर दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल को लेकर उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में औद्योगिक विकास, नगर विकास, ऊर्जा, राजस्व, परिवहन, पीडब्लूडी, वन, उच्च शिक्षा आदि विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ मेरठ कमिश्नर अनीता सी मेश्राम, डीएम अनिल ढींगरा आदि शामिल हुए। एनसीआरटीसी के जीजीएम सुधीर कुमार शर्मा की ओर से बैठक में रैपिड रेल प्रोजेक्ट को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया। इसमें बताया गया कि दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर कुल 82.15 किलोमीटर का है। इसमें 68.03 किलोमीटर एलिवेटेड होगा और 14.12 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा। ऐसी स्थिति में रैपिड रेल को लेकर जमीन अन्य प्रोजेक्ट के मुकाबले कम चाहिए। दिल्ली से मेरठ के बीच दुहाई और मोदीपुरम में डिपो बनाने के लिए थोड़ी अधिक जमीन चाहिए।

वहीं, रिठानी, मुरादनगर में जमीन चिह्नित है। बस उसे ट्रांसफर करने की जरूरत है। रिठानी में एमडीए की जमीन बताई गई तो मुरादनगर में सिंचाई विभाग की जमीन है। इस पर मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों से कहा कि रैपिड रेल का यह प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार के लिए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। किसी भी विभाग में कोई बाधा है तो उसे जल्द से जल्द निस्तारित कराया जाए।

एक किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगी

खिचड़ीपुर से साहिबाबाद (बीईएल कपंनी) तक करीब एक किलोमीटर रैपिड रेल नाले के नीचे से गुजरेगी। इसके लिए नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (एनसीआरटीसी) ने नगर निगम से एनओसी मांगी है। नगर निगम के मुख्य अभियंता ने एनओसी देने से पहले अध्ययन शुरू कर दिया। निगम की तरफ से जल्द एनओसी दे दी जाएगी।

रैपिड रेल पर जल्द काम शुरू होना है।

गाजियाबाद में रैपिड रेल एक किलोमीटर अंडरग्राउंड गुजरेगी। इसके लिए एनसीआरटीसी ने एनओसी मांगी है। एनओसी जल्दी दे दी जाएगी।

-मोइनुद्दीन, मुख्य अभियंता, नगर निगम

एनसीआरटीसी अधिकारियों ने कहा कि निर्माण कार्यों के लिए टेंडर आदि की कार्रवाई हो चुकी है। मई के अंत में साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर क्षेत्र में काम प्रारंभ कर देना है। कमिश्नर ने जानकारी दी कि स्थानीय स्तर पर विभागों की बैठक हो चुकी है। शासन स्तर पर जमीन का मामला विचाराधीन है। मुख्य सचिव ने इस पर कार्रवाई के लिए कहा।